भारत की नीति के संबंध में अमरीकी कूटनीतिज्ञ के विचार

*55. **श्री सौमयपाल : क्या विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 जुलाई, 1995 के "इंडियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें एक अमरीकी कूटनीतिज्ञ, डा० हेनरी कीसिंजर ने भारत के भावी विस्तारवादी दृष्टिकोण के संबंध में कतिपय आशंकायें व्यक्त की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार भारत के बारे में इस प्रकार के दुष्प्रचार का मामला डा० किसिंजर के साथ उठाना चाहेगी जिसके कारण आशंकाओं को बल मिल रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी (क) जी, हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) डा० हेनरी किसिंगर द्वारा दिये गये वक्तव्य में उनके वैयक्तिक विचार व्यक्त हुए हैं। उनके ये विचार अमरीका की आधिकारिक नीति से संबंद्ध वक्तव्य नहीं है। सरकार की निजी व्यक्तियों के वक्तव्यों के संबंध में प्रतिक्रिया देने की परम्परा नहीं है।

दिल्ली में बहुमंजिला इमारतों में आग लगने की घटनाएं

*56. **श्री अनन्तराम जायसवाल:** क्या गृह मंत्री 17 मई, 1995 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न 6231 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास दिल्ली में बहुमंजिला इमारतों में आग लगने की घटनाओं का कोई ब्यौरा है जिनके कारण प्रति वर्ष जान-माल की हानि होती है और सरकारी कागजात नष्ट हो जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों (30 जून, 1995 तक) के दौरान हुई ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या सुरक्षात्मक उपाय करने का निर्णय लिया है तथा सरकार द्वारा लिए गए/लिए जाने वाले निर्णय का कार्यान्वयन कब से होगा?

गृह मंत्री (श्री एम०बी० चव्हाण): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जुलाई, 1992 से जून, 1995 तक की अवधि के दौरान बहुमंजिली इमारतों में आग लगने की 213 घटनाएं सूचित की गई जिनमें एक व्यक्ति मारा गया तथा लगभग 7.37 करोड़ रुपये मूल्य की सम्पत्ति का नुकसान हुआ।

समुचित सुरक्षा व्यवस्था की न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा न करने वाली सभी बहुमंजिली इमारतों के मालिकों/दखलदारों को समय-समय पर दिल्ली अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 1986 के अधीन नोटिस जारी किए जाते हैं। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान्यतः तीन माह का समय दिया जाता है।

Wild Life in Terai Region

*57. SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of INVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the report which appeared in the Indian Express of June 25, 1995 captioned, "Gypsy-borne marauders hold sway in Terai";

(b) is so, what is Government's information about the large scale depredation on wild life in Terai region and devastation caused to the forests there; and

(c) what effective steps have been taken by the Central and State Governments to protect the ecology, wild life and forests?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) Yes, Sir.

(b) The U.P. Forest Department has reported that there is no large scale depredation of wildlife in Terai region. However, sporadic cases of poaching of wild animals have been reported on which action is taken under the provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972.

(c) On receiving reports about several cases of poaching of wild animals in western Uttar Pradesh, the Central Government took up the matter with the State Govt. to ensure that effective protection is provided to the wildlife and forests to control poaching incidents. The State Govt. have informed that they have identified 17 sensitive forest divisions in the Terai region where the staff have been provided with vehicles for better mobility, wireless sets for better communication and are equipped with arms and ammunition. A Forest Protection Force has also been created and deployed for intensive patrolling in the forest areas of these divisions to guard against the cases of poaching and illegal tree felling. A Forest protection force has also been created and deployed for intensive patrolling in the forest areas of these divisions to guard against the cases of poaching and illegal tree felling.

E-Mail service in Cities

*58. SHRIMATI MALTI SHARMA:
SHRI RAJ NATH SINGH:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government have started electronic mail service in the county;

(b) if so, the cities where the service has been started so far; and

(c) the cities likely to be covered under this service during 1995?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) The Government have introduced a scheme for licensing registered Indian Companies to operate E-Mail service in the country. So far 11 companies have already been given such licences and 6 companies have commenced the service.

(b) and (c) Details are given in the statement.

Statement

Name of the cities, where service has commenced	Name of the additional cities where service is likely to be commenced during 1995
1. Ahmedabad	1. Aurangabad
2. Bangalore	2. Bhuvaneswar
3. Baroda	3. Calicut
4. Bhavnagar	4. Chandigarh
5. Bombay	5. Faridabad
6. Calcutta	6. Ghaziabad
7. Cochin	7. Guahati
8. Coimbatore	8. Jaipur
9. Delhi	9. Jamshedpur
10. Hosur	10. Jodhpur
11. Hyderabad	11. Kanpur
12. Indore	12. Lucknow
13. Madras	13. Ludhiana